चावल और गेहूं की मांग, इनके आवंटन और उठान निम्नानुसार है:—

जिन्स	मांग	आवंटन	उठान
चावल	1500 टन	1500 टन	नगण्य
गेहूं	17000 टन	12000 टन	6200 टन

जनवरी, 1996 से प्रभावी पंजाब का लेवी चीनी का मासिक कोटा 8619 टन बैठता है जिसे दिसम्बर, 96, जनवरी, 97 और फरवरी, 97 के लिए 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था जैसाकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के आवंटन अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, उनकी सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति, केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, मौसमी उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन अनुपूरक होते हैं और ये किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समस्त मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

पंजाब सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन 1.1.96 से 1991 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-समान मानदण्ड के आधार पर किए जा रहे हैं और ये उनकी मांग के आधार पर नहीं किए जाते हैं।

एफ०सी०आई० की आर्थिक लागत

1545. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक-लागत में विगत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान गेहूं और चावल की आर्थिक-लागत की अनुमानित राशि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1996-97 में आर्थिक-लागत का पूर्वानुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) 1993-94 से 1996-97 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडल किए गए गेहूं और चावल की इकानमिक लागत निम्नानुसार है:—

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	इकानामिक लागत गेहूं	चावल
1993-94	532.03	665.10
1994-95	551.17	694.71
1995-96 (संशोधित अनुमान)	563.57	746.72
1996-97 (संभावित)	650.00	811.00

देश में औद्योगिक जिले

1546. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में राज्य-वार विशेषकर गुजरात राज्य में औद्योगिक जिलों की संख्या कितनी-कितनी हो जायेगी;

(ख) उन जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) "उद्योग रहित जिला" योजना, 1983 के तहत, जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) कार्य योजना, 1979-80 के अनुसार देश में कुल 93 जिलों की "उद्योग रहित जिलों" के रूप में पहचान की गई थी। गुजरात में डांगरा जिले की पहचान ऐसे जिले के रूप में की गई थी जिसे "उद्योग रहित जिले" की सूची में शामिल किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व 9 एन आई डी केन्द्रों को पूरा किया गया था तथा 2 एन आई डी केन्द्रों को भारत सरकार द्वारा जून, 1988 में प्रारंभ की गई नई विकास केन्द्र योजना के तहत विकास केन्द्रों में बदल दिया गया था ताकि एन आई डी योजना, जो बन्द कर दी गई थी, को बदला जा सके।

(ग) और (घ) विकास केन्द्र योजना के तहत देश-